



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032025-261952  
CG-DL-E-26032025-261952

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2025/ चैत्र 4, 1947

No. 88]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2025/ CHAITRA 4, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025

मामला सं. एडी (ओआई) – 05/2025

विषय: चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, सऊदी अरब साम्राज्य और ताइवान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "इथाइलीन डायमाइन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत के संबंध में।

फा. सं. 6/05/2025—डीजीटीआर – समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रूप में भी कहा गया है) के अनुसार, मेसर्स बालाजी स्पेशियलिटी कैमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' या 'याचिकाकर्ता' के रूप में भी कहा गया है) द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष, चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, सऊदी अरब साम्राज्य और ताइवान (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' के रूप में भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "इथाइलीन डायमाइन" (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तुएं' अथवा ('पीयूसी') के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित किए गए आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "इथाइलीन डायमाइन" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया है।

**क. विचाराधीन उत्पाद**

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) 'इथाइलीन डायमाइन' अर्थात् 'ईडीए' है। यह उत्पाद एक स्पष्ट रंगहीन लिक्विड है। इसका फ्रीजिंग प्वाइंट 11 °C और बॉइलिंग प्वाइंट 117 °C है।
4. ईडीए दो रिएक्टिव अमाइन ग्रुप का एक रसायन है, जिसके कारण यह विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में एक आवश्यक घटक हो जाता है। ईडीए को मुख्य रूप से विशेष कंपाउंड, फंगीसाइड्स, कृषि रसायन, कोटिंग और पॉलिमर जैसे रसायनों का उत्पादन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा, उत्पाद का व्यापक उपयोग कृषि रसायनों, फार्मास्यूटिकल आदि जैसे उद्योगों में किया जाता है।
5. ईडीए को टैरिफ वर्गीकरण के उप-शीर्ष 2921 21 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 अर्थात् "कार्बनिक रसायन" के तहत वर्गीकृत किया गया है। आवेदक ने यह कहा है कि ईडीए को एचएस कोड 29212100 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
6. आवेदक ने किसी पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच के लिए पक्षकार इस जांच की शुरुआत किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कर सकते हैं और पीसीएन, यदि कोई हो तो, उसका प्रस्ताव कर सकते हैं।

**ख. समान वस्तु**

7. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पादों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है तथा दोनों ही समान वस्तुएं हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, आवश्यक उत्पाद विशिष्टताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशिष्टताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का ही बदल बदल कर उपयोग कर सकते हैं और करते रहे हैं। दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसीलिए, नियमावली के तहत उन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए।
8. इस प्रकार से, वर्तमान जांच की शुरुआत करने के प्रयोजनों के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को *प्रथम दृष्टया* संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

**ग. घरेलू उद्योग और आधार**

9. यह आवेदन मेसर्स बालाजी स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा, एक अन्य उत्पादक, अर्थात् मेसर्स डायमाइन्स एंड केमिकल्स लिमिटेड भी है। आवेदक ने यह दावा किया है कि मेसर्स डायमाइन्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कोई उत्पादन नहीं कर रहा है। इस संबंध में मेसर्स डायमाइन्स एंड केमिकल्स लिमिटेड को पत्र भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
10. आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध वस्तुओं का न तो कोई आयात किया है और न ही वह संबद्ध देशों के निर्यातकों अथवा भारत में आयातकों के साथ संबद्ध है।
11. प्रदान की गई सूचना के आधार पर, यह देखने में आया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य से 'घरेलू उद्योग' में आता है और यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

**घ. संबद्ध देश**

12. वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, सऊदी अरब साम्राज्य और ताइवान हैं।

**ड. जांच की अवधि**

13. जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 (12 माह) तक की है। क्षति जांच की अवधि 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि है।

**च. कथित पाटन का आधार****i. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य**

14. आवेदक ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का हवाला दिया है और यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए तथा चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए कि निर्देशित किया जाना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में प्रबल है। जब तक चीन जन. गण. समिति के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि बाजार अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थितियां मौजूद हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध- I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
15. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक उस कीमत का सवाल है जिस पर विचाराधीन उत्पाद बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को बेचा गया है, आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि अधिकांश देशों से निर्यात मूल्य अनुमानित उत्पादन लागत से कम है। इसलिए, आवेदक किसी अन्य देश से निर्यात मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। इसलिए आवेदक ने भारत से ईडीए के अपने निर्यात मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदक ने भारत में उत्पादन की अपनी लागत के अनुसार सामान्य मूल्य के बारे में जानकारी भी प्रदान की है, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया गया है। जांच शुरू करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने भारत में एसजीए व्यय और लाभ के लिए उचित समायोजन के साथ उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

**ii. यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य**

16. आवेदक ने यूरो स्टेट के अनुसार इंटर यूरोपीय संघ कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि यह वह कीमत है जिस पर उत्पाद का यूरोपीय संघ में उपभोग के लिए व्यापार किया जाता है। जांच की शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्ताव किए गए सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

**iii. सऊदी अरब साम्राज्य के लिए सामान्य मूल्य**

17. आवेदक ने यह दावा किया है कि उसके पास सऊदी अरब साम्राज्य में बिक्री कीमत के संबंध में किसी भी साक्ष्य तक पहुंच नहीं है। अतः आवेदक ने भारत में उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के साथ विधिवत रूप से समायोजित किया गया है। जांच की शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

**iv. ताइवान का सामान्य मूल्य**

18. आवेदक ने दावा किया है कि ताइवान के घरेलू बाजार में उत्पादकों के वास्तविक विक्रय मूल्य के संबंध में उनके पास कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उत्पाद का ताइवान में एक समर्पित कोड है।
19. इसलिए, आवेदक ने ताइवान में आयात मूल्य को सामान्य मूल्य के रूप में मानने का प्रस्ताव किया है। यह वह मूल्य है जिस पर ताइवान में उपभोक्ता ने किसी अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता से सामग्री खरीदी है और इसे सामान्य मूल्य के आधार के रूप में माना जा सकता है। आरंभिक उद्देश्य के लिए, प्राधिकरण ने आवेदक द्वारा प्रस्तावित सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

**v. निर्यात कीमत**

20. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात संबंधी आंकड़ों में उल्लिखित सीआईएफ मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय क्रेडिट लागत और वस्तुसूची ले जाने की लागत के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

**vi. पाटन मार्जिन**

21. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया यह स्थापित करता है कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

**छ. क्षति का साक्ष्य और कारणात्मक संबंध**

22. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। घरेलू उद्योग ने विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के कथित पाटित आयातों के कारण हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आयातों की मात्रा में निरपेक्ष अवधि के साथ-साथ सापेक्ष अवधि में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की कीमतों पर सकारात्मक मूल्य कटौती और मूल्य अवसाद का प्रभाव पड़ा है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को भारी घाटा, नकद घाटा, नकारात्मक पीबीआईटी और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल हुआ है। विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के पाटित आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से, उत्पादन और घरेलू बिक्री में गिरावट आई है। आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य और बिक्री लागत दोनों से कम है। विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

**ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

23. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित किए गए आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्टि प्राप्त करने के बाद तथा अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उपयुक्त राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

**झ. प्रक्रिया**

24. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

**ञ. सूचना की प्रस्तुति**

25. सभी पत्राचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते <dir13-dgtr@gov.in>, <dd19-dgtr@gov.in> और <ad12-dgtr@gov.in> पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए, जिसकी एक प्रति <consultant-dgtr@nic.in> और <dir15-dgtr@gov.in> पर भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्व योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड फॉर्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फॉर्मेट में हों।
26. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार और भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दाखिल कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित फॉर्मेट और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

27. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित फॉर्मेट और तरीके से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है।
28. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका एक अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराना आवश्यक है।
29. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे सूचना के साथ-साथ जांच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन और अवगत रहें।

#### ट. समय सीमा

30. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित ईमेल पत्तों <dir13-dgtr@gov.in>, <dd19-dgtr@gov.in> और <ad12-dgtr@gov.in> पर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए, जिसकी एक प्रति <consultant-dgtr@nic.in> और <dir15-dgtr@gov.in> पर ऐसी तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस तारीख को आवेदक द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों का अगोपनीय पाठ निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा अथवा नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
31. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के लिए उत्तर दाखिल करें।
32. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल किए जाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारणों का प्रदर्शन करना चाहिए तथा ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

#### ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

33. जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। इसका पालन न किए जाने पर उत्तरों/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।
34. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकन किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी तथा प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
35. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं, तथा/ अथवा अन्य सूचना, जिसके लिए ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए, जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, तो सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध किया जाना चाहिए अथवा खाली स्थान रखा जाना चाहिए (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं हो) और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित रूप से संक्षेप में दिया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है।

37. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सारांश को उपयुक्त रूप से समझने के लिए गोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश किए जाने के लिए अति संवेदनशील नहीं है और इस प्रकार का सारांश संभव नहीं है, तो इसके कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
38. हितबद्ध पक्षकार अनुरोध के गोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता से संबंधित मामले पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
39. नियमावली के नियम 7 के अनुसार सार्थक गोपनीय पाठ अथवा पर्याप्त और उचित कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध और गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
40. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच किए जाने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में इसका प्रकटीकरण करने के लिए अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।

#### ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

41. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, साथ ही उन सभी से यह अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध का अगोपनीय पाठ परिचालित न किए जाने पर हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना जा सकता है।

#### ड. असहयोग

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर अथवा प्राधिकारी द्वारा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है अथवा अन्यथा प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न करता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

#### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2025

Case No. AD (OI) – 05/2025

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Ethylene Diamine” originating in or exported from China PR, European Union, Kingdom of Saudi Arabia and Taiwan - reg.**

**F. No. No. 6/05/2025-DGTR—** Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (*hereinafter referred as the ‘Act’*) and the Customs Tariff (*Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury*) Rules, 1995, as amended from time to time (*hereinafter referred to as the ‘Rules’*), M/s Balaji Speciality Chemicals Limited (*hereinafter referred to as the ‘applicant’ or ‘petitioner’*) has filed an application before the Designated Authority (*hereinafter referred to as the ‘Authority’*), for initiation of an anti-dumping investigation on imports of “Ethylene Diamine” (*hereinafter referred to as the ‘product under consideration’ or ‘subject goods’ or ‘PUC’*), originating in or exported from China PR, European Union, Kingdom of Saudi Arabia and Taiwan (*hereinafter referred to as the ‘subject countries’*).

2. The applicant has alleged that material injury is being caused due to the dumped imports of the subject goods from the subject countries and has requested for the imposition of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

**A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

3. The product under consideration (PUC) in the present investigation is '**Ethylene Diamine**', abbreviated as "**EDA**". The product is a clear colour less liquid. It has a freezing point at 11 °C and a boiling point of 117 °C.
4. EDA is a chemical with two reactive amine groups, making it an essential ingredient in various industrial processes. EDA is primarily used in the production of chemicals such as specialty compounds, fungicides, agrochemicals, coatings, and polymers. Further, the product is widely utilized in industries such as agrochemicals, pharmaceuticals, and etc.
5. EDA is classified under Chapter 29 viz., "**Organic chemicals**" of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 2921 21 of the tariff classification. The applicant has stated that EDA is imported under the HS code 2921 21 00. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.
6. The applicant has not proposed any PCN methodology. The parties to the present investigation may provide their comments, on the scope of the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

**B. LIKE ARTICLE**

7. The applicant has submitted that there are no significant differences in the product produced by the applicant and those exported from the subject countries, and both are like articles. The product produced by the applicant and those imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules.
8. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the product produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject countries.

**C. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

9. The application has been filed by M/s Balaji Speciality Chemicals Limited. Apart from the applicant, there is another producer namely M/s Diamines & Chemicals Limited. The applicant has claimed that the M/s Diamines & Chemicals Limited is not undertaking any production. In this regard, a communication was sent to M/s Diamines & Chemicals Limited, but no response has been received.
10. The applicant has further certified that they have not imported the subject goods nor related to the exporters from the subject countries or importers in India.
11. Based on the information provided, it is seen that the applicant constitutes 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

**D. SUBJECT COUNTRY(IES)**

12. The subject countries in the present investigation are China PR, European Union, Kingdom of Saudi Arabia and Taiwan.

**E. PERIOD OF INVESTIGATION**

13. The period of investigation (POI) for the investigation is from 1<sup>st</sup> October, 2023 to 30<sup>th</sup> September, 2024 (12 months). The injury investigation period will cover the period 1<sup>st</sup> April, 2021 to 31<sup>st</sup> March, 2022, 1<sup>st</sup> April, 2022 to 31<sup>st</sup> March, 2023, 1<sup>st</sup> April, 2023 to 31<sup>st</sup> March, 2024 and the POI.

**F. BASIS OF ALLEGED DUMPING**

**i. Normal value for China PR**

14. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.

15. The applicant has submitted that data relating to cost and price in market economy third country is not available. As regards the price at which the product under consideration has been sold from the market economy third country to any other country, including India, the applicant submitted the export price from majority of the countries is below the estimated cost of production. Therefore, the applicant could not determine normal value based on export price from any other country. The applicant has therefore claimed normal value on the basis of its export price of EDA from India. The applicant has also provided information on normal value as per its cost of production in India, duly adjusted to include a reasonable profit margin. For the purpose of initiation, the Authority has considered normal value based on cost of production with reasonable adjustments for SGA expenses and profit in India.

**ii. Normal value for European Union**

16. The applicant has claimed normal value based on the intra European Union prices as per Euro Stat. The applicant has claimed that this is the price at which the product is traded for consumption in European Union. For the purpose of initiation, the Authority has considered normal value as proposed by the applicant.

**iii. Normal value for Kingdom of Saudi Arabia**

17. The applicant has claimed that they do not have access to any evidence of selling price in the Kingdom of Saudi Arabia. Therefore, applicant has determined the normal value based on the best estimates of cost of production in India, duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin. For the purpose of initiation, the Authority has considered normal value based on cost of production in India.

**iv. Normal value of Taiwan**

18. The applicant has claimed that they do not have access to any evidence regards to actual selling price of the producers in the domestic market of Taiwan. Further, it is submitted by the applicant that the product has a dedicated code in Taiwan.
19. Therefore, the applicant has proposed to consider import price into Taiwan as normal value. This is the price at which consumer in Taiwan have bought the material from an international supplier and can be considered as a basis for normal value. For the purpose of initiation, the Authority has considered normal value as proposed by the applicant.

**v. Export price**

20. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DGCI&S transaction wise import data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses credit costs and inventory carrying costs.

**vi. Dumping margin**

21. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin with respect to the product under consideration imported from the subject countries is not only above the *de minimis* level but is also significant. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

**G. EVIDENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK**

22. Information furnished by the domestic industry has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The domestic industry has furnished *prima facie* evidence with respect to the injury suffered because of the alleged dumped imports of subject goods from subject countries. The volume of imports has increased in absolute term as well as in relative term. There is positive price undercutting and price depression effect on the prices of the domestic industry. As a result, the domestic industry has incurred severe losses, cash losses, negative PBIT and negative return on capital employed. The increase in the dumped imports of subject goods from subject countries has led to decline in the market share, production and domestic sales of the domestic industry. The landed price of imports is below both the selling price and cost of sales of the domestic industry. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject countries.

**H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION**

23. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link



between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

## **I. PROCEDURE**

24. The provisions stipulated in Rule 6 of the Rules shall be followed in the present investigation.

## **J. SUBMISSION OF INFORMATION**

25. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses <dir13-dgtr@gov.in>, <dd19-dgtr@gov.in> and <ad12-dgtr@gov.in> with a copy to <consultant-dgtr@nic.in> and <dir15-dgtr@gov.in>. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
26. The known producers/exporters in subject countries, the government of subject countries through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
27. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
28. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
29. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

## **K. TIME LIMIT**

30. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses <dir13-dgtr@gov.in>, <dd19-dgtr@gov.in> and <ad12-dgtr@gov.in> with a copy to <consultant-dgtr@nic.in> and <dir15-dgtr@gov.in> within 30 days from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the applicant would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
31. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
32. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

## **L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

33. Where any party makes any confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the same may lead to rejection of the response / submissions.
34. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
35. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

36. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (*where indexation is not possible*) and such information must be appropriately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
37. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
38. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the submission.
39. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
40. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

**M. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

41. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions might lead to consideration of an interested part as non-cooperative.

**N. NON-COOPERATION**

42. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority